



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

No - 158, 159, 160
See page - 760

भाग II—खण्ड 3—पारा-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1993/वैशाख 8, 1915

No. 157] NEW-DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1993/VAISAKHA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1993

सं. को. नि. 388(की)।—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त विविधों का प्रश्नोत्तर हुए और कम्पनी विधि बोर्ड के संदर्भ में (अर्हताएँ और अवधार) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाएं जो ऐसे अधिक्रमों से पूर्व के गई हैं या करने से रह गई हैं, अधिक्रम करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों के संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएँ, अनुभव और अन्य सेवा शर्त) नियम, 1993 है।

2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदूत होंगे।

परिमाणांश—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न हो।

- (क) "अध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ख) "कम्पनी विधि बोर्ड" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन पठित कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) "कम्पनी विधि सेवा" से केंद्रीय कम्पनी विधि सेवा नियम 1965 के नियम 3 के अधीन गतिश केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा अभिप्रेत है;
- (घ) "न्यायिक सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "सदस्य" से न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी हैं;
- (च) "तकनीकी सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है;
- (छ) "उपाध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।
- 3. सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और आयु-सीमा
- (1) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अन्तिम तर्जी होना चाहिए।

(क) भारत के राजपद्धति में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो या कुल 10 वर्ष का अवधि तक कोई न्यायिक पद धारित न कर चुका हो और धारण: अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाई न रह चुका हो; या

(ग) कम्पनी विधि सेवा (विधिक शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या चयन श्रेणी में कोई पद या उस सेवा की श्रेणी 1 में कोई पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(घ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा की श्रेणी 11 में कोई पद कम से कम तीन वर्ष तक या उस सेवा में कोई उच्चतर पद धारण किए हुए हैं या धारण किए हुए था;

(2) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हत नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) कम्पनी विधि सेवा (लेखा शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या चयन श्रेणी में कोई उच्चतर पद कम से कम 8 वर्ष तक पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(ख) केन्द्रीय कम्पनी वृत्त स्कीम के अधीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र न हो जिसके वैतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वैतनमान से कम न हो और कम्पनी विधि से संबंधित समस्याओं के निपटान के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो; या

(ग) कम से कम 15 वर्ष तक चार्टेड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(घ) कम से कम 15 वर्ष तक लाभता और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन लाभता लेखाकार के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(ड.) कम से कम 15 वर्ष तक कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (45क) में यथा परिस्थित पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव न रखता हो और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य है।

(३) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने पैतालिस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

(४) कोई व्यक्ति उपायक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने सदस्य के रूप में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक पद धारण न किया हो।

(५) कोई व्यक्ति अवधि के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न हो या न रहा हो, अवधि होने के लिए अर्हत न हो; या

(ख) उसने उपायक के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक पद धारण न किया हो।

4. भर्ती की पद्धति :—(1) सदस्यों का चयन भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके निर्देशितों के परामर्श से किया जाएगा।

(2) इस नियम की कोई बात, कम्पनी विधि बोर्ड, के अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जो इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस रूप में कृत्य कर रहा है, नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

5. विकित्सक दृष्ट्या योग्यता:—कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति किए जाने वाले विकित्सा बोर्ड द्वारा विकित्सक दृष्ट्या योग्य घोषित नहीं कर दिया जारा है, यदि उसे किसी सुन्दर अधिकारी द्वारा पहले ही योग्य घोषित न कर दिया हो।

6. किसी सदस्य द्वारा पद त्यागः—कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अर्थात् हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही पद छोड़ने के अनुसार नहीं कर दिया गया हो, ऐसा सूचना का अनुदित्त तरिके से तान मास समाप्त होने तक वह पदों क्षमता के रूप में संभव रूप से नियुक्त व्यक्ति के अनन्ता पद ग्रहण करने तक या उसने पद की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पूर्वतम हो, पद धारण करता रहेगा।

7. कुछ परिस्थितियों में सदस्यों का पद से हटाया जाना—केन्द्रीय सरकार भारत के गुरुत्व-न्यायवाद के परामर्श से किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकता है।

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णय किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष घरहराया था या जिसमें केन्द्रीय सरकार का राय में, नैतिक अधिमता अंतविलित है; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मोर्चासिक रूप से अवश्य हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभवना है; या

(ड.) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

परन्तु इस नियम के कोई बात किसी ऐसे अवधिकारी को लागू नहीं होगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है।

परन्तु यह आर जि जहां किसी सदस्य को खंड (ख.) से खंड (ड.) तक में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर हटाए जाने की प्रस्तावना है वहां उस सदस्य को उसके विवर आरोपी के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपी के बाबत सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

8. अवधि और सदस्यों के पद की अवधि:—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबोधित है उसके सिवाय, अवधि या उपायक तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

9. वैतन और भत्ते:—(1) अवधि को प्रति मास 8, (नियम) वैतन का संदाय किया जाएगा।

(2) उपाध्यक्ष को 7300-100-7600 रु. के बेतनमान में बेतन का सदाय किया जाएगा।

(3) सदस्य को 5800-200-6700 रु. बेतनमान में बेतन का सदाय किया जाएगा।

(4) अधिकारी श्रीरामसदन वे भर्ते लेने के हस्तार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के बहु-वर्तन या बेतनमान वाला संग्रह के पद धारण कर रहे अधिकारी को अनुचित हैं।

10. नियम (1)---यदि इन नियमों के निर्विवाद के तंत्रमें कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विविध विवरण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

11. व्यावृति---इन नियमों के कोई वात केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित पर लारा किए गए अदायों के अनुसार अनुचित और अनुचित जनजातियों, भूत्तुर्वासीनिकी और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्त्तों के लिए उत्तराधिकारी किए जाने के लिए अधिकारी आरक्षण आप सभी में छुट आर अन्य विवरणों पर प्रमाण नहीं डालेगा।

12. पद और योग्यता का शपथ---अधिकारी या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, द्वारा पद नामग्रह करने से पूर्व, इन नियमों से उपबंध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और योग्यता का शपथ लेना और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

13. सेवा का अन्वयता :—ऐसे विषयों की बाबत किसी सदस्य की सेवा का अन्वयता, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है वैसी ही होती जायी कि उस समवय मार्ग सरकार के बताने हैसियत के अन्य कर्मचारियों को लागू है।

प्रलेप 1

(नियम 12 देखिए)

कल्पना: विधि बोर्ड के अध्यक्ष, अपाध्यक्ष, सदस्य के लिए पद योग्यता का प्रलेप ।

“मैं, अनुकूल, जिसे कल्पना: विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि मैं इन्द्रिय, उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठानुरूप और शृद आकरण से अपने मर्दों की योग्यता, जातकार्य और विवेकवृद्धि के अनुग्रह, मय या प्रत्यात, अनुरा या वैभवस्य के बिना, निर्वहन करूँगा।”

प्रलेप 2

(नियम 12 देखिए)

कल्पना: विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के लिए योग्यता का शपथ का प्रलेप।

“मैं, अनुकूल, जिसे कल्पना: विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कोई निमाविषय, जिसे जबत कल्पना: विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में मेरे विविध रूप द्वारा जाएगा या जो मैं जानता हूँगा, किसी अवित्त या व्यक्तियों की, तब के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के संधर्क निर्वहन के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।”

[फाइल सं. ए-- 12018/3, 92-एडी-I]

जो. वैक्टरियन, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1993

GSR 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Company Law Board Members (Qualifications and Experience) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely,—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Chairman” means Chairman of the Company Law Board;

(b) “Company Law Board” means the Board of Company Law Administration constituted under sub-section (1) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) “Company Law Service” means the Central Company Law Service constituted under rule 3 of the Central Company Law Service Rules, 1965;

(d) “Judicial Member” means a Judicial Member of the Company Law Board;

(e) “Member” means a Judicial Member or Technical Member and includes the Vice-Chairman and the Chairman;

(f) “Technical Member” means a Technical Member of the Company Law Board;

(g) “Vice-Chairman” means Vice-Chairman of the Company Law Board.

3. **Qualifications and age limit for appointment of Members:**—(1) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he—

(a) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or

(b) has, for at least ten years, been an Advocate of High Court, or has partly held judicial office and has been partly in practice as an Advocate for a total period of ten years; or

(c) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Legal Branch) and is holding, or has held, a post in Super-Time Grade or Selection Grade in that Service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(d) is, or has been a Member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade II of that Service for at least three years, or any higher post in that Service;

(2) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he—

(a) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Accounts Branch) and is holding, or has held, a post in Super-Time Grade or Selection Grade in that service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(b) is eligible to be appointed as a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme, or to any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, and has adequate knowledge of and experience in dealing with the problems relating to Company Law; or

(c) is, or has been, for at least fifteen years in practice as a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(d) is, or has been, for at least fifteen years in practice as a Cost Accountant under the Costs and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959); or

(e) has, for at least fifteen years, working experience as a Secretary in whole time practice as defined in clause (45A) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and is a member of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(3) A person shall not be eligible for appointment as Member unless he has completed the age of forty five years.

(4) A person shall not be eligible for appointment as Vice-Chairman unless he has for a period of not less than two years held office as Member.

(5) A person shall not be eligible for appointment as Chairman unless he—

(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(b) has for a period of not less than three years held office as Vice-Chairman.

4. Method of recruitment:—(1) The selection of Members shall be made by the Government of India in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.

(2) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman or any Member of the Company Law Board functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. Medical Fitness.—No person shall be appointed as a Member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

6. Resignation by a Member.—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time.

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earliest.

7. Removal of members from office in certain circumstances:—The Central Government, in consultation with Chief Justice of India, may remove from office any Member, who—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided that nothing contained in this rule shall apply to a Chairman who is a Judge of a High Court.

Provided, further, that where a Member is proposed to be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

8. Term of office of Chairman and Members:—Except as provided in rule 6 or rule 7, the Chairman or Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty two years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty years.

9. Salary and allowances:—(1) The Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000 per month (fixed);

(2) The Vice-Chairman shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 7300-100-7600;

(3) A Member shall be paid a salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.

(4) The Chairman and Members shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government officer holding Group 'A' post carrying the same pay or scale of pay.

10. Interpretation:—If any question arises relating to the interpretation of these rule, the same shall be referred to the Central Government for its decision.

11. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Oaths of office and secrecy:—Every person appointed to be Chairman or a Vice-Chairman or a Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

13. Other conditions of Services:—The conditions of service of a Member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

FORM I

(See rule 12)

Form of oath of office for Chairman|Vice-Chairman| Member of the Company Law Board.

“I, A.B., having been appointed as Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman|Vice Chairman|Member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour affection or ill-will.”

FORM II

(See rule 12)

Form of oath of secretary for Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board.

“I, A.B., having been appointed as Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board, do solemnly affirm|do swear in the name of God, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman|Vice-Chairman|Member of the said Company Law Board except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman|Vice-Chairman|Member.”

[File No. A-12018|3|92-Ad.II]

G. VENKATARAMANAN, Addl. Secy.

